दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO :- CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, मंगलवार 09 जुलाई 2019 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-01, अंक-277

यमुना एक्सप्रेस-वे पर लखनऊ से दिल्ली आ रही बस नाले में गिरी, 29 की मौत

आगरा (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के आगरा में सोमवार तड़के लखनऊ से दिल्ली जा रही राज्य परिवहन निगम की डबल डेकर बस यमुना-एक्सप्रेस वे पर झरना नाले में गिरने से 29 लोगों की मौत हो गई और 18 घायल हो गये।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस हादसे में यात्रियों की मौत पर दुख जताते हुए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को घायलों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। उन्होंने घायलों के बेहतर इलाज के लिए भी निर्देश दिए गये हैं।

सूत्रों ने बताया है कि लखनऊ से दिल्ली आनंद विहार जा रही अवध डिपो की जनरथ बस डबल डेकर बस एत्मादपुर क्षेत्र में

यमुना-एक्सप्रेस वे पर तड़के करीब साढ़े चार बजे झरना नाले में गिर गई। मृतकों में 27 पुरुष, एक महिला और बालक शामिल है। दुर्घटनाग्रस्त बस और सभी लोगों को नाले से निकाल लिया गया है। नाले में अभी तलाश की जा रही है कहीं कोई यात्री एवं उनका सामान तो नाले में नहीं है।

घायल 18 लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घायलों में दो की हालत गंभीर है। मृतकों की शिनाख्त कराई जा रही। प्रथम दृष्ट्या चालक को झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ। बस पुल की रैलिंग तोड़कर करीब 15 फिट नाले में जा गिरी।

हादसे की सूचना मिलते ही बचाव एवं राहत का काम शुरु कर दिया गया था। वह पुलिस बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और घायलों को शवों को नाले से निकलवाया। उन्होंने बताया शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और इसके लिए डाक्ट्रों की तीन टीमें गठित की गई हैं।

एक्सप्रेसवे दुर्घटना पर राजनाथ ने आदित्यनाथ से बात की

दिल्ली आ रही एक बस के यमुना एक्सप्रेसवे पर एक नाले में गिरने से 29 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जिसके कुछ घंटों बाद ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की है। घटना पर दुख प्रकट करते हुए राजनाथ ने ट्वीट किया, यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई बस दुर्घटना में कई लोगों की मृत्यु के दुखद समाचार से मैं व्यथित हूं। दुर्घटना के संबंध में आदित्यनाथ से मैंने बात की है। उन्होंने प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा एवं (परिवहन) मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को दुर्घटना स्थल पर भेजा है।

उन्होंने आगे कहा, भाजपा के प्रदेश महामंत्री पंकज सिंह भी घटनास्थल पर गए हैं। इस हृदय विदारक घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी भावनायें एवं संवेदनाएं प्रेषित करता हूं तथा जो लोग घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूं।

लखनऊ से दिल्ली आ रही बस यमुना एक्सप्रेस वे पर तड़के लगभग 4.15 बजे डिवाइडर से टकराकर दो फ्लाइओवरों के बीच 40 फीट नीचे बह रहे नाले में गिर गई।

महत्वपूर्ण एवं खास

राज्यसभा में सुदर्शन अग्रवाल को श्रद्धांजलि

नईदिल्ली (आरएनएस)। राज्यसभा ने आज अपने पूर्व महासचिव सुदर्शन अग्रवाल को श्रद्धांजलि दी। सभापति एम वेंकैया नायडु ने सदन की कार्यवाही शुरु होते ही अग्रवाल के निधन की जानकारी दी। अग्रवाल का तीन जून को निधन हो गया था। उनका जन्म 1931 में पंजाब में हुआ था। अग्रवाल वर्ष 1956 में न्यायिक सेवा में आये थे और 1981 में राज्यसभा के महासचिव बनाये गये थे। वह उत्तराखंड और सिक्किम के राज्यपाल भी रहे थे। वह कई सामाजिक और शैक्षणिक संस्थानों से भी जुड़े थे। बाद में सदस्यों ने मौन खड़े होकर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस दुर्घटना में लोगों के मारे जाने पर शोक व्यक्त किया

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के आगरा में बस दुर्घटना में 29 लोगों के मारे जाने पर दु:ख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट संदेश में कहा, 'उत्तर प्रदेश के आगरा में हुई बस दुर्घटना से दु:खी हूं। उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन प्रभावितों को हर संभव मदद उपलब्ध करा रहा है'। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के आगरा में सोमवार तड़के लखनऊ से दिल्ली जा रही राज्य परिवहन निगम की डबल डेकर बस यमुना-एक्सप्रेस वे पर झरना नाले में गिरने से 29 लोगों की मौत हो गई और 18 घायल हो गये।

रेल की पटरी पार करते हुए पकड़े गए तो जाना होगा जेल

नईदिल्ली (आरएनएस)। रेलवे हादसों को बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. देश भर में बड़े पैमाने पर फुटओवर ब्रिज व रोड अंडर ब्रिज बनाए जा रहे हैं ताकि लोगों को पटरियां न पार करनी पड़े. यदि आप कुछ मिनट बचाने के लिए फुट ओवर ब्रिज नहीं चढ़ते हैं और आलस के चलते एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए रेल की पटरी पार करने का प्रयास करते हैं तो आपकी मुश्किल बढ़ सकती है. इस काम में जान जाने का जोखिम तो है ही इसके अलावा यदि जान नहीं भी जाए तो आपको जेल जाना पड़ सकता है. वहीं देश भर में बड़े पैमाने पर अभियान चला कर पटरी पार करने वालों को पकड़ा जा रहा है. रेल की पटरियों को पार करना कानूनी तौर पर भी अपराध है. रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत रेल की पटरियों को पार करने के अपराध में व्यक्ति को पकड़ा जा सकता है. ऐसा करते हुए पाए जाने पर व्यक्ति को 06 महीने तक की सजा हो सकती है. वहीं 1000 रुपये तक जुर्माने का भी प्रावधन है. गौरतलब है कि देश भर में रेलवे में होने वाले हादसों में पटरी पार करते हुए लोगों की सबसे अधिक मौत होती है. इसी लिए रेलवे की ओर से देश भर में बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चला कर लोगों को पटरी पार न करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है.

भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त, हाईटाइड की चेतावनी, उड़ानें प्रभावित

मुंबई (आरएनएस)। भारी बारिश और खराब दृश्यता के कारण मुंबई हवाई अड्डे पर सोमवार को उड़ान परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के एक प्रवक्ता ने कहा कि दृश्यता कम-ज्यादा होने के कारण उड़ानों के परिचालन संबंधी कोई गतिविधि नहीं हुई। हालांकि, कोई उड़ान रद्द नहीं की गई, लेकिन कम से कम तीन उड़ानों को अन्य हवाईअड्डों की ओर डायवर्ट कर दिया गया। बारिश से जुड़ी एक अलग घटना में, शिवाजी नगर में एक ग्राउंड-प्लस वन फ्लोर वाला घर गिरने से आठ लोग घायल हो गए। जहां तीन महिलाएं राजावाडी अस्पताल में भर्ती हैं, वहीं पांच अन्य का पहले ही इलाज हो चुका था। वहीं मौसम विभाग की ओर से मुंबई में आज भी समुद्र में हाईटाइड की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार मुंबई में सोमवार शाम 4:18 बजे हाईटाइड आएगा।

पश्चिम बंगाल में 100 से ज्यादा देसी बम बरामद, 9 गिरफ्तार

कोलकाता (आरएनएस)। पश्चिम बंगाल में रविवार को पुलिस ने 100 से ज्यादा जिंदा देसी बम बरामद किए और अवैध हथियार रखने के आरोप में नौ लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने यह जानकारी दी। दस दिनों के भीतर मल्हारपुर और लाभपुर में दो अलग-अलग विस्फोटों के बाद बीरभूम जिले में पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। यह जिला राजनीतिक हिंसा के लिए चर्चित है।

हालांकि इन विस्फोट में कोई भी घायल नहीं हुआ क्योंकि वे खाली इमारतों में हुए थे लेकिन इसने 2017 के विस्फोट की याद दिला दी जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई थी। बीरभूम पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने कहा, हमने बीरभूम क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों से 100 से अधिक जिंदा बम बरामद किए हैं।

उन्होंने कहा, बम निरोधक दस्ते के जवानों ने बमों को सफलतापूर्वक डिफ्यूज कर दिया है। जिले भर में रात भर की गई छापेमारी के दौरान नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे छह अवैध आग्नेयास्त्र जब्त किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा, हमने लाभपुर विस्फोट मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। आगे की जांच जारी है। विस्फोट की प्रकृति का पता लगाने के लिए फोरेंसिक टीम को बुलाया गया था।

सार्वजनिक परिवहन पर हरित पर्यावरण के लिए जोरः सीतारमण

नईदिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वित्त वर्ष 2019-20 के केंद्रीय बजट में जीवाश्म ईंधन और इलेक्ट्रिक कारों पर करों के प्रस्ताव से लोग प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों से बचेंगे और वे या तो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग करेंगे या सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करेंगे। सीतारमण ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बजट पेश करते हुए पेट्रोल और डीजल पर कर मध्य वर्ग को दुखी करने के लिए नहीं, बल्कि पर्यावरणीय चिंताओं को देखते हुए बढ़ाए गए हैं। मंत्री ने कहा, मैं अगर मेट्रो की बेहतर कनेक्टिविटी, सार्वजनिक परिवहन और भविष्य के बेहतर परिवहन के लिए निवेश कर रही हूं, तो मैं एक कार में एक सवार की अपेक्षा सार्वजनिक वाहनों के उपयोग में व्यावहारिक बदलाव की उम्मीद करूंगी। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि कच्चे तेल की कीमतों में नरमी से पेट्रोल और डीजल पर अतिरिक्त विशेष उत्पाद शुल्क और सड़क और बुनियादी ढांचे के उपकर को एक रुपये प्रति लीटर बढ़ाने की गुंजाइश हो गई है।

उन्होंने कहा, मैंने किफायती घर खरीदने की लोगों को सहूलियत देने के लिए अगर कर घटाए हैं, तो क्या यह धनाड्य लोगों के लिए किया है? बिल्कुल नहीं, यह मध्य वर्ग के लिए है। मैंने अगर जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक कारों के उपयोग को बढ़ावा दिया है तो यह पर्यावरण के प्रति हमारी बचनबद्धता के मद्देनजर है। मैं जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों को लाकर भी मध्य वर्ग की मदद कर रही हूं।

केंद्र सरकार ने 2019-20 के बजट में पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्क में दो प्रतिशत वृद्धि का प्रस्ताव किया है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को रफ्तार देने और वाणिज्यिक क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाने के लिए सरकार ने बजट में फास्टर एडोप्शन एंड मैन्यूफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दूसरे चरण (फेम-2 योजना) के लिए 10,000 करोड़ रुपये व्यय करने की घोषणा की है।

50 भारतीय मजदूर इराक में फंसे,पासपोर्ट भी छीना

» जॉब एजेंट्स की धोखाधड़ी का शिकार

हैदराबाद (आरएनएस)। तेलंगाना के शहर मंचेरियन के 50 से अधिक युवकों के एजेंटों की धोखाखड़ी और मानव तस्करी के गिरोह का शिकार होने का मामला सामने आया है। खबरों के मुताबिक, इन सभी युवकों को इराक के शहर इरबिल में रखा गया है और जबरदस्ती काम कराया जा रहा है। बताया जाता है कि तेलंगाना के इन युवकों को नौकरी का लालच देकर विजिटर वीजा पर इराक ले जाया गया था और इन सभी लोगों को इराक में अच्छी नौकरी दिलाने का वादा किया गया था, लेकिन इराक में उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करने को मजबूर होना पड़ रहा है।

मंचेरियल के कावल गांव के रहने वाले इन लोगों के परिजनों का आरोप है कि कागजी कार्रवाई में फंसाकर उन्हें इराक में रहने को मजबूर किया जा रहा है। यही नहीं इन लोगों को बार-बार स्थानीय प्रशासन की कार्रवाई से होकर भी गुजरना पड़ रहा है। बताया जाता है कि इरबिल में फंसे इन भारतीयों में से दो को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जेल में डाल दिया है।

पकड़े गए भारतीयों के परिजनों ने जब उन्हें गिफ्तार करने के बारे में पूछा तो उन्हें कुछ भी बताने से इनकार कर दिया गया। परिजनों को अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी है कि उन्हें किस अपराध में पकड़ा गया है। परिजनों का आरोप है कि नौकरी न होने के कारण लोग इस तरह के झांसे में फंस रहे हैं।

परिजनों का आरोप है कि जिस एजेंट ने इन लोगों को इराक में नौकरी दिलाने का वादा किया था, उसने भरोसा दिलाया था कि उन्हें 50 हजार रुपये प्रति माह दिया जाएगा। हालांकि इराक पहुंचते ही इन सभी लोगों के पासपोर्ट एजेंट्स ने ले लिए और इन्हें कम पैसों में काम कराने पर मजबूर किया गया।

व्हाइट हाउस को "अयोग्य" बताने वाले ब्रिटेन के शीर्ष राजदूत पर ट्रम्प ने किया पलटवार

लंदन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और उनके प्रशासन को ''अयोग्य'' और ''बेकार'' बताने वाले ब्रिटेन के राजदूत किम डोराक पर ट्रम्प ने रविवार को पलटवार किया और वहीं ब्रिटेन ने लीक हुए राजनयिक ज्ञापनों के संबंध में जांच शुरू की है। लीक हुए राजनयिक ज्ञापनों में यह दावा किया गया, जिसे रविवार को समाचार पत्र 'मेल' ने प्रकाशित किया।

ट्रम्प ने कहा कि राजदूत डोराक ने '' ब्रिटेन की अच्छी सेवा नहीं की और वह और उनका प्रशासन राजदूत का बड़ा प्रशंसक नहीं है। डोराक ने कथित तौर पर कहा, '' हमें नहीं लगता कि उनका प्रशासन अधिक सामान्य, कम बेकार, कम अप्रत्याशित, गुटबाजी से कम ग्रस्त, कूटनीतिक रूप से कम अनाड़ी या कम अयोग्य हो पाएगा।''

खबर के अनुसार राजदूत किम डोराक ने कहा कि ट्रम्प का राष्ट्रपति कार्यकाल ''खत्म हो सकता है'' और उसका ''अपमानजनक अंत'' हो सकता है ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह लीक राजनयिक ज्ञापनों के संबंध में औपचारिक जांच करेगा।

राजधानी के चार बड़े अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल, सेवाएं बाधित

नईदिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के चार बड़े अस्पतालों में डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं. लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल सहित गोविंद बल्लभ पंत (जीबी पंत), मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज और गुरुनानक आई सेंटर के डॉक्टरों ने काम बंद कर दिया है. ये सभी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेल के इमरजैंसी वार्ड में ड्यूटी पर तैनात एक डॉक्टर के साथ मरीज के परिजनों द्वारा की गई मारपीट का विरोध कर रहे हैं.

सुबह से हड़ताल पर गए डॉक्टर अस्पतालों में सुरक्षा की मांग कर रहे हैं. वहीं अस्पतालों में चरमराई स्वासथ्य सेवाओं को देखते हुए दिल्ली सरकार स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने बैठक बुलाई है. जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन और एमएस एलएनजेपी बातचीत कर रहे हैं.

जुलाई में ही दिल्ली के बाड़ा हिंदु राव अस्पताल में हुई मारपीट की घटना के विरोध में डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी थी. अस्पताल के सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स ने काम करना बंद कर दिया था. सुरक्षा की मांग कर रहे डॉक्टरों का कहना था, अस्पताल प्रशासन एक पुलिस चौकी लगाने की बात कर रहें हैं लेकिन हमें गार्ड्ज़ की संख्या में बढ़ोतरी भी चाहिए. अगर लिखित में हमारी मांग मान ली जाती है तो ठीक है वरना जब तक ऐसा नहीं होता है हम काम पर नहीं लौटेंगे.

सिंधिया और देवड़ा ने दिया इस्तीफा

» एक दिन में कांग्रेस को दो बड़े झटके

नईदिल्ली (आरएनएस)। लोकसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पार्टी में बड़े नेताओं के बीच इस्तीफा देने की जैसी होड़ लग गई है। अब कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर अपने इस्तीफे की जानकारी दी। इससे पहले आज मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष मिलिंद देवड़ा ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफे का ऐलान करते हुए ट्वीट किया, जनादेश स्वीकार करते हुए और हार की जिम्मेदारी लेते हुए मैंने राहुल गांधी को कांग्रेस महासचिव पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। मैं उन्हें (राहुल गांधी) इस जिम्मेदारी को सौंपने के लिए और मुझे पार्टी की सेवा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

कैबिनेट सचिव ने 5000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था की तैयारी के लिए बैठक बुलाई

नईदिल्ली (आरएनएस)। कैबिनेट सचिव पी.के. सिन्हा ने 2015 तक देश की अर्थव्यवस्था 5000 अरब (5 ट्रिलियन) डॉलर करने का लक्ष्य पूरा करने के लिए विजन, नीतियों, निवेश और विभागीय जिम्मेदारियों पर चर्चा करने के लिए सोमवार को बैठक बुलाई है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को 2019-20 केंद्रीय बजट भाषण में इसकी घोषणा की थी। सिन्हा ने बैठक में समूहों- सामाजिक, स्वास्थ्य, वित्त और आर्थिक के आठ सचिवों को लिया गया है जो इस लक्ष्य को पाने और विभागों की जिम्मेदारियां तक करने के लिए अपना रोडमैप प्रदर्शित करेंगे।

केजरीवाल ने दिए भ्रष्ट अधिकारियों की सूची तैयार करने के निर्देश

नईदिल्ली (आरएनएस)। पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग की दिए गए निर्देशों के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवल ने भी शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है. सीएम केजरीवाल ने अपने सभी कैबिनेट सदस्यों को अपने-अपने विभागों के भ्रष्ट अधिकारियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए हैं. ताकि इन सभी को जबरन सेवानिवृत्ति (कंपलसरी रिटायरमेंट) दी जा सके.

जानकारी के मुताबिक दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने शनिवार को मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मीटिंग के लिए बुलाया. जिसमें दोनों से दिल्ली के भ्रष्ट अधिकारियों और बाबुओं पर कार्रवाई करने को लेकर चर्चा की. इसके बाद सीएम ने दिल्ली के मुख्य सचिव से विस्तार से बातचीत करने के बाद निर्देश जारी किए.

अरविंद केजरीवाल ने एलजी के साथ हुई बैठक में साफ कर दिया कि वे भी दिल्ली में ऐसे बाबुओं और अधिकारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाएंगे. ऐसे अधिकारियों को सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) के फंडामेंटल रूल 56 (जे) के तहत जबरन रिटायरमेंट दिया जाएगा.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2013-14 में अपने पहले 49 दिनों के कार्यकाल में भी भ्रष्ट अधिकारियों पर नकेल कसी थी. वहीं अपने दूसरे कार्यकाल में भी केजरीवाल ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति काफी सख्त रहे हैं. केजरीवाल का कहना है कि ऐसे अधिकारियों की वजह से लोककल्याणकारी नीतियां प्रभावित होती हैं.

दिल्ली में सरकारी मशीनरी से भ्रष्टाचार हटाने के लिए एलजी अनिल बैजल ने हाल ही में प्लान तैयार किया था. इतना ही नहीं उन्होंने दिल्ली में तैनात दागी और भ्रष्ट अफसरों को कंपल्सरी रिटायरमेंट देने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए. एलजी बैजल की ओर से मुख्य सचिव, पुलिस आयुक्त, डीडीए उपाध्यक्ष और तीनों निगमों के आयुक्तों को पत्र लिखा गया.